छोटे शहर और बड़े ख्वाब

मुंबई-दिल्ली नहीं, शेयर बाजार में छोटे शहरों की बढ़ती पकड़

नई दिल्ली, 23 अगस्त. देश में शेयर बाजार अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे महानगरों की कहानी नहीं रह गया है. छोटे और मझोले शहरों के निवेशक तेजी से इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा जारी जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक, नए निवेशक रजिस्ट्रेशन में टियर-2 और टियर-3 शहरों की हिस्सेदारी 36% तक पहुंच गई है. यानी हर 100 नए निवेशकों में से करीब 36 लोग छोटे शहरों से जुड़ रहे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि यह उछाल ऐसे दौर में देखने को मिल रहा है, जब ईरान-अमेरिका तनाव, टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता और ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव लगातार सुर्खियों में हैं. इसके बावजूद छोटे शहरों से निवेशकों की लगातार बढ़ती एंट्री यह बताती है कि डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, आसान और सस्ती ट्रेडिंग सुविधा और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बढ़ने से निवेश की दुनिया का दायरा काफी बड़ा हो गया है.

बड़े शहरों का दबदबा कायम, लेकिन दायरा फैला

आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में हुए कुल नए निवेशक रजिस्ट्रेशन में टॉप-10 जिलों की हिस्सेदारी 17.5% रही, जबकि टॉप-50 जिलों को मिलाकर यह आंकड़ा 36.7% तक पहुंच गया. इससे साफ है कि नए निवेशक अब सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के कई हिस्सों में तेजी से जुड़ रहे हैं. बड़े शहरों में दिल्ली-एनसीआर सबसे आगे रहा, जहां 70.1 हजार नए निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया. यह कुल नए रजिस्ट्रेशन का 5.3% है. इसके बाद मुंबई का नंबर आता है, जहां 46.2 हजार यानी 3.5% नए निवेशक जुड़े.

गुजरात के दो बड़े शहरों में तेज उछाल

मंथली आधार पर निवेशकों की संख्या में सबसे तेज उछाल गुजरात के दो बड़े शहरों में देखने को मिला. अहमदाबाद में महीने-दर-महीने नए निवेशकों की संख्या में 49.3% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई, वहीं सूरत में यह आंकड़ा 38.2% रहा. इसके अलावा बेंगलुरु और जयपुर में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जहां बेंगलुरु में 16.7% और जयपुर में 16.6% की मंथली ग्रोथ दर्ज हुई. हालांकि, जब इन आंकड़ों को सालाना आधार पर देखा गया तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई. टॉप-10 जिलों में से कोई भी शहर सालाना आधार पर पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज नहीं कर सका.

ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भी निवेश जारी

सबसे खास बात यह है कि निवेशकों की यह बढ़ती दिलचस्पी ऐसे समय में सामने आ रही है जब ग्लोबल लेवल पर हालात बहुत सामान्य नहीं हैं. ईरान-अमेरिका तनाव, अमेरिका के टैरिफ और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता के चलते शेयर बाजार में लंबे समय से उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ऐसे माहौल में आमतौर पर निवेशक सतर्क हो जाते हैं, लेकिन इसके उलट छोटे शहरों से जुड़ने वाले नए निवेशकों की संख्या बढ़ रही है. यह इस बात का संकेत है कि निवेशकों का बाजार पर भरोसा और रिस्क लेने की क्षमता बढ़ी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप से आसान ट्रेडिंग, कम फीस वाले डीमैट अकाउंट और सोशल मीडिया व यूट्यूब के जरिए बढ़ती फाइनेंशियल एजुकेशन ने छोटे शहरों के लोगों के लिए शेयर बाजार तक पहुंच आसान कर दी है. पहले जहां शेयर बाजार में निवेश को बड़े शहरों के पढ़े-लिखे और अमीर लोगों से जोड़कर देखा जाता था, अब यह सोच तेजी से बदल रही है.

स्काईवेज एयर सर्विसेज का आईपीओ आज खुलेगा

नई दिल्ली, 23 अगस्त. मेनबोर्ड सेगमेंट में स्काईवेज एयर सर्विसेज का आईपीओ 24 अगस्त को खुलने वाला है. कंपनी का इरादा 582.80 करोड़ जुटाने का है. इस इश्यू में 398.80 करोड़ के 2.89 करोड़ नए शेयर जारी होंगे. साथ ही 184 करोड़ के 1.33 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) रहेगा. ओएफएस में कंपनी के प्रमोटर यशपाल शर्मा, तरुण शर्मा और निवेशक हिमांशु छाबड़ा, रोहित सहगल शेयरों को बिक्री के लिए रखेंगे. आईपीओ में बोली लगाने के लिए प्राइस बैंड 131-138 प्रति शेयर है. लॉट साइज 100 शेयर है. इश्यू की क्लोजिंग 27 अगस्त को होगी.

थोक बाजार में चीनी-तेल की कीमतों में उछाल

चीनी एक सप्ताह में 323 रुपये महंगी, सरसों तेल 218 रुपये चढ़ा

नई दिल्ली, 23 अगस्त. घरेलू थोक जिंस बाजार में बीते सप्ताह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला. चीनी और सरसों तेल के भाव में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि चावल की कीमत भी बढ़ी. दूसरी ओर गेहूं के दाम में गिरावट रही. दालों और अन्य खाद्य तेलों में सप्ताह के दौरान उतार-चढ़ाव बना रहा.

सप्ताहभर के कारोबार में चीनी की औसत कीमत 323 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई. मीठे के बाजार में गुड़ की कीमत में भी 777 रुपये प्रति क्विंटल की बड़ी तेजी रही और सप्ताहांत पर इसका औसत भाव 5,570 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया. खाद्य तेलों में सरसों तेल के भाव में 218 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई, जिससे इस वर्ग में भी तेजी का रुख दिखाई दिया. चावल की कीमत में भी मजबूती रही. सप्ताह के दौरान इसकी औसत कीमत 49 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर सप्ताहांत में 4,105 रुपये प्रति क्विंटल हो गई. चावल की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई जब अन्य प्रमुख अनाज में समान रुख नहीं रहा. गेहूं के बाजार में सप्ताह के दौरान नरमी रही. इसकी औसत कीमत 22 रुपये प्रति क्विंटल घटकर 2,838 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई. इस तरह एक ही सप्ताह में प्रमुख खाद्यान्नों के बाजार में विपरीत रुझान देखने को मिला.

थोक बाजार के साप्ताहिक आंकड़ों से स्पष्ट है कि खाद्य जिंसों में कीमतों की चाल एक समान नहीं रही. चीनी, गुड़, सरसों तेल और चावल में तेजी रही, जबकि गेहूं कमजोर हुआ. दालों तथा दूसरे खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव ने बाजार को मिला-जुला बनाए रखा. आने वाले दिनों में इन जिंसों की कीमतों पर मांग, उपलब्धता और बाजार की कारोबारी परिस्थितियों का असर महत्वपूर्ण रहेगा.

प्याज एक हफ्ते में 11% महंगा

बफर स्टॉक से बिक्री शुरू होने पर घटेंगे प्याज के दाम

आवक में देरी होने से कीमतों पर दबाव

मुंबई, 23 अगस्त. दक्षिण भारत से खरीफ फसल की आवक में देरी के बीच प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव (महाराष्ट्र) में प्याज की थोक कीमतें उछलकर 35 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. व्यापारियों का कहना है कि देर से बुआई के कारण दक्षिण भारत से खरीफ प्याज की फसल की आवक में देरी होने से कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

राहत की बात यह है कि जल्द ही कीमतें जल्द नीचे आ सकती हैं. उपभोक्ता मामले के विभाग के मुताबिक, 21 अगस्त को प्याज का औसत खुदरा मूल्य 40.72 रुपये प्रति किलो है. 17 अगस्त को यह 37.20 रुपये प्रति किलो था. एक महीने पहले 34.87 रुपये प्रति किलो था. उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे के अनुसार जमाखोरों पर शिकंजा कसने के लिए बफर स्टॉक से बिक्री शुरू करने की योजना तैयार की गई है. सरकार द्वारा सितंबर के पहले सप्ताह में बफर स्टॉक का प्याज बेचना शुरू करने की उम्मीद है. विभाग रोजाना प्याज की मांग, आपूर्ति और कीमत पर नजर रख रहा है. इस महीने कोई बड़ा त्योहार और विवाह सीजन नहीं है. ऐसे में प्याज की मांग सीमित है, लेकिन फिर भी कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कृत्रिम रूप में प्याज का संकट पैदा किया जा रहा है. यही वजह है कि अभी बफर स्टॉक नहीं निकाला जा रहा है. जल्द ही सरकार कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर देगी. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इससे पहले भी बफर स्टॉक जनता के लिए खोला जा सकता है. देश में सालाना 3.10 करोड़ टन प्याज का उत्पादन होता है.

विदेशी निवेशकों की वापसी भारतीय शेयरों पर भरोसा

एफपीआई की वापसी से बाजार में नई जान

नई दिल्ली, 23 अगस्त. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अब फिर भारत लौट आए हैं. लगातार चार महीनों तक भारी निकासी के बाद वे अब खुलकर भारतीय शेयरों पर दांव लगा रहे हैं.

इस बदले हुए रुख के दम पर एफपीआई ने अगस्त के शुरुआती हफ्तों में ही भारतीय इक्विटी मार्केट में ?23,544 करोड़ की भारी-भरकम पूंजी झोंक दी है. जुलाई में भी उन्होंने 20,200 करोड़ का शुद्ध निवेश किया था. विदेशी निवेशकों की इस नई निवेश रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आमतौर पर बड़े लार्ज-कैप और सुरक्षित माने जाने वाले हैवीवेट शेयरों पर दांव लगाने वाले विदेशी फंड्स इस बार अलग राह पर हैं. वे मिडकैप शेयरों में ज?यादा पैसा लगा रहे हैं.

कंपनियों के मजबूत पहली तिमाही के वित्तीय नतीजों, भारतीय रुपये में आई स्थिरता और अर्थव्यवस्था की ठोस वृद्धि संभावनाओं ने विदेशी फंड्स का भरोसा एक बार फिर बहाल किया है. विदेशी निवेशकों की यह हालिया खरीदारी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि मार्च से जून के बीच भारतीय इक्विटी की जमकर बिकवाली की थी. जुलाई और अगस्त की लगातार खरीदारी के बावजूद साल 2026 में विदेशी निवेशक अब तक कुल ?2,30,000 करोड़ की पूंजी निकाल चुके हैं, जो साल 2025 की कुल 1,66,000 करोड़ की निकासी से भी अधिक है.

6 साल बाद यूपीआई पर लौटेगा एमडीआर

यूपीआई पेमेंट अब पूरी तरह फ्री नहीं, 2000 से ऊपर लगेगा चार्ज

नई दिल्ली, 23 अगस्त. एकीकृत भुगतान अंतरफलक यानी यूपीआई से भुगतान को लेकर करीब छह साल बाद बड़ा बदलाव होने की संभावना है.

शून्य व्यापारी छूट दर व्यवस्था खत्म होने के बाद 2,000 रुपये या उससे अधिक के यूपीआई व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन पर 0.3 प्रतिशत व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर लगाया जा सकता है. प्रस्तावित शुल्क का उद्देश्य यूपीआई से जुड़े बैंकों, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और अन्य संस्थाओं को डिजिटल भुगतान नेटवर्क को बनाए रखने और मजबूत करने में होने वाली लागत की कुछ भरपाई करना है. हालांकि सरकार ने संकेत दिया है कि इसका सीधा बोझ ग्राहकों और छोटे कारोबारियों पर नहीं डाला जाएगा. यूपीआई की शुरुआत के बाद डिजिटल भुगतान को तेजी से बढ़ावा देने के लिए एमडीआर को धीरे-धीरे कम किया गया और 2020 में इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया. इसके बाद दुकानदारों से यूपीआई भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं लिया जाता था. अब बढ़ते डिजिटल लेनदेन, साइबर सुरक्षा और भुगतान ढांचे पर बढ़ते खर्च के बीच बड़े मूल्य वाले लेनदेन पर शुल्क वापस लाने की संभावना है.

महिंद्रा ओजा भविष्य की बागवानी को दे रहा नई दिशा

खेती के लिए कॉम्पैक्ट और हल्के 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों को बढ़ावा

मुंबई, 23 अगस्त। महिंद्रा समूह के प्रतिष्ठित और भारत के नंबर-1 ट्रैक्टर ब्रांड महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने ओजा प्लेटफॉर्म के तीन वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया. ओजा प्लेटफॉर्म ने भारत में बागवानी और अन्य विशेष कृषि कार्यों के लिए कॉम्पैक्ट एवं हल्के फोर-व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों को अपनाने को गति दी है.

हर्ष राय - सीईओ, महिंद्रा ट्रैक्टर्स और परीक्षित घोष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रमुख - मार्केटिंग और राष्ट्रीय व्यवसाय संचालन, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, ओजेए ट्रैक्टर रेंज के साथ.(बाएं से दाएं).

भविष्य की कृषि जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित ओजा कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर रेंज 21 से 30 एचपी श्रेणी में उपलब्ध है. इसे विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली कृषि और विशिष्ट खेती के कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है. अंगूर के बाग, फलों के बगीचे, गन्ना और कतार वाली फसलों में उपयोग के लिए ओजा कॉम्पैक्ट आकार, बेहतर गतिशीलता, सटीक नियंत्रण और बेहतरीन पावर-टू-वेट अनुपात प्रदान करता है. 4 डब्ल्यूडी तकनीक इसे विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर पकड़ और स्थिरता देती है.

महिंद्रा ट्रैक्टर्स के सीईओ हर्ष राय ने कहा कि खेती का भविष्य विशेष जरूरतों के अनुरूप तैयार तकनीक आधारित समाधानों में है. बागवानी और विशेष कृषि क्षेत्रों के तेजी से विस्तार के साथ उद्देश्य आधारित मशीनीकरण की आवश्यकता बढ़ रही है. ओजा प्लेटफॉर्म में विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग, नवाचार और किसानों की जरूरतों को एक साथ लाकर आधुनिक कृषि की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि महिंद्रा भविष्य के लिए तैयार ऐसे उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो किसानों को प्रत्येक एकड़ से अधिक उत्पादन हासिल करने में सक्षम बनाएं. महिंद्रा ट्रैक्टर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं हेड, मार्केटिंग और नेशनल बिजनेस ऑपरेशंस परीक्षित घोष ने कहा कि ओजा ने बागवानी, अंगूर के बाग, फलों के बगीचों, गन्ने और अन्य विशेष कृषि कार्यों से जुड़े किसानों के बीच पसंदीदा विकल्प के रूप में अपनी जगह बनाई है.

समाचार विशेष

अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दांव!

इमरान मसूद के परिवार में सेंधमारी, दामाद शायान मसूद की सपा में धमाकेदार एंट्री

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। सहारनपुर से कांग्रेस के चर्चित सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये.

सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. शायान मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सहारनपुर से

कांग्रेस से सांसद रहे काजी रशीद मसूद के पोते हैं. इस दौरान अखिलेश यादव से शायान मसूद उनके पिता शादान मसूद के साथ विधायक उमर अली और पूर्व विधायक माविया अली भी मौजूद रहे. मंगलवार को ही सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की एक बैठक में बहस हुई थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ. ऐसे में शायान मसूद की सपा में एंट्री काफी अहम मानी जा रही है. बता दें, शायान मसूद की समाजवादी पार्टी में एंट्री पिछले कुछ समय से लटकी थी. गुरुवार को अखिलेश यादव ने उनको पार्टी में शामिल करा दिया.

बैठक में इमरान मसूद-आशु मलिक में झड़प

मंगलवार शाम को ही सहारनपुर में विकास भवन के सभागार में हुई बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने सड़क और अधूरे नाले को लेकर सपा विधायक ने सवाल उठाया. इस पर कांग्रेस सांसद भड़क गए.

सुनील बंसल नहीं बनेंगे सांसद

नई दिल्ली. नितिन नबीन की नई टीम के महामंत्रियों में से सुनील बंसल इकलौते महामंत्री हैं, जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है. वे पिछली टीम में भी महामंत्री थे. पिछली टीम से दो ही लोग नई टीम में रिपीट हुए हैं, जिनमें से एक वे हैं. पहली बार महामंत्री बनने के बाद से ही इस बात की चर्चा है कि वे संसद के किसी सदन में जाएंगे या नहीं. यह चर्चा इस बार भी है लेकिन कहा जा रहा है कि वे सांसद नहीं बनेंगे. ध्यान रहे सुनील बंसल संघ से भाजपा में आए हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली महामंत्री रहे हैं.

पंजाब फतह पूनिया के लिए चुनौती

चंडीगढ़. भाजपा हाईकमान ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया को पंजाब भाजपा का प्रभारी नियुक्त किया है. पूनिया को हरियाणा भाजपा का प्रभारी रहते हुए यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पार्टी की पंजाब में चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. पूनिया के सामने हरियाणा मॉडल के सहारे पंजाब में भी भाजपा को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है.

पूनिया हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी जीत के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं. वह साल 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के प्रभारी थे. साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी पूनिया हरियाणा के कोऑर्डिनेटर थे.

राजनीतिक मामलों के जानकार जगतार सिंह भुल्लर कहते

क्या हरियाणा मॉडल के सहारे खिला पाएंगे कमल?

हैं कि हरियाणा मॉडल को पंजाब में लागू करना आसान नहीं होगा. दोनों राज्यों की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां भिन्न हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पंजाब में सक्रिय हैं. सैनी का प्रचार और पूनिया की रणनीति से पंजाब भाजपा को चुनाव में लाभ मिल सकता है. भुल्लर के अनुसार, हाईकमान ने पंजाब में पार्टी के नए और पुराने कैडर में संतुलन स्थापित किया है. नए प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की पृष्ठभूमि साल 2022 से पहले कांग्रेसी थी. वहीं, नए प्रभारी सतीश पूनिया भाजपा कैडर के हैं.

पंजाब भाजपा के अध्यक्ष हाल ही में बदले गए हैं. पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष बनाया गया है. ढिल्लों की नई टीम में कई पुराने भाजपा नेताओं को दरकिनार किया गया है. इससे पार्टी के कुछ नेताओं में मनमुटाव चल रहा है. पूनिया को संगठन मजबूत करने के साथ-साथ सभी नेताओं को एकजुट करना होगा. उन्हें साल 2027 में भाजपा की जीत के लिए एक मजबूत नींव तैयार करनी पड़ेगी. पूनिया के लिए भाजपा को पंजाब में शहरी पार्टी की छवि से उभारना एक बड़ी चुनौती है.

वापसी

राज्य बार काउंसिल चुनाव में शानदार प्रदर्शन, भाजपा को पछाड़कर दर्ज की बंपर जीत

चुनाव में हार के बाद टीएमसी का धमाकेदार कमबैक

कोलकाता, 23 अगस्त. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद यह चर्चा थी कि अब तृणमूल कांग्रेस का बंगाल से सफाया हो जाएगा. इसी सोच के साथ टीएमसी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ भी छोड़ दिया और अपनी पार्टी भी बना ली.

हालांकि, अब पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनाव के नतीजे आने के बाद यह बात साफ हो गई है कि टीएमसी अभी भी जिंदा है. इस चुनाव में टीएमसी

ने बंपर जीत हासिल कर भाजपा को चेताया है कि टीएमसी अभी खत्म नहीं हुई है और वो कभी भी कमबैक कर सकती है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद बार काउंसिल चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी ने राहत की सांस ली है. दरअसल, बुधवार को बार काउंसिल चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें टीएमसी ने 23 में से 15 सीटों पर जीत दर्ज की. टीएमसी के मुकाबले भाजपा और कांग्रेस जरा भी नहीं टिक पाई. इस चुनाव में भाजपा ने तीन सीटें जीती, लेफ्ट फ्रंट ने भी तीन तो वहीं कांग्रेस ने दो सीटों पर जीत हासिल की. पश्चिम बंगाल बार काउंसिल की कुल 23 सीटों के लिए चुनाव हुआ था. इस चुनाव में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने 15 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं भारतीय जनता पार्टी को तीन सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा. जहां भाजपा नहीं टिकी वहां लेफ्ट फ्रंट को तीन सीटें मिलीं और कांग्रेस पार्टी तो दो सीटों पर ही सिमट गई.

भाजपा और सुवेंदु अधिकारी को लगा झटका

बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा का मानना था कि अब राज्य में पार्टी का दबदबा होगा और बार काउंसिल चुनाव में भी भाजपा की विजय होगी. इस सोच के बाद अचानक से अपनी आंखों के सामने पार्टी की बड़ी हार देखना सीएम सुवेंदु अधिकारी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों के तहत, बार काउंसिल की 23 सीटों में से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं. इन आरक्षित सीटों में से टीएमसी ने चार और कांग्रेस ने एक सीट जीती.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक / निविदा / 26 / 1589 ::ई-टेंडर आमंत्रण सूचना:: सिरोंज दिनांक 21/08/2026

नगर पालिका परिषद सिरोंज जिला विदिशा द्वारा निम्न कार्य हेतु आन लाईन निविदा का आमंत्रण किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है -

टेंडर क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि रू	ऑनलाईन निविदा का प्रपत्र मूल्य	समय अवधि
1	2	3	4	5	6
2026_UAD_530060_1	वार्ड 03 गणेश राम लोधी से द्वारका प्रसाद कुर्मी तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	24,34,372	18,500	5000	03 माह

शर्त-टेंडर डाक्यूमेंट के आधार पर निर्धारित सभी कर एवं शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी.कटौत्रा किया जावेगा।

निविदा प्रपत्र क्रय, डाउनलोड करने एवं निविदा से सम्बंधित समस्त शर्तें एवं जानकारी https://mptenders.gov.in एवं नगरपालिका परिषद सिरोंज जिला विदिशा के लोक निर्माण विभाग शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सिरोंज